

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग І---खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रहा**शित**

PUBLISHED BY AUTHORITY

#i∘ 89]

नई बिल्ली, मंगलवार, ग्रप्रेल 25, 1972/वैशन्त 5, 1894

No. 89]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 1972/VAISAKHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी दाति है दि हुई, कि यह इ.स.र संब सन श्रं रूप में र सा, दार से है।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 25th April, 1972

No. F.16013/2/71-TexF.—The Government of India by a Resolution dated the 27th February, 1971, adopted the following prices of rayon tyreyarn/cord/fabrics upto 31st December, 1971:

Prices for rayon tyre yarn/cord/fabrics ex-works exclusive of excise duty

-	Yarn	Cord	Rupces per kg.) Fabrics
Super II materials	12.25	00. EI	13,50
Super I materials	10.25	00, II	11,50

^{2.} The Government had also indicated in the above quoted Resolution that demand/supply/market situation obtaining towards the beginning of the third quarter of 1971 would be analysed so as to secure fixation of prices after 31st December, 1971. Government have requested the Tariff Commission to undertake this analysis. Pending the receipt of the report. Government have decided to continue for the present the prices as detailed in para 1 above.

K. KISHORE, Jt. Secy.

बिदेश ब्याप र मत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली. 25 भगेल 1972

सं॰ एक॰ 16013/2/71-दरस एक.--भारत सरकार ने, दिनांक 27 फरवरी, 1971, के संकल्प के अनुपार 31-12-1971 तक रेयन टायर धार्ग/कार्डं/फेंब्रिक्स की निम्नलिखित कीमर्ले स्वीकार की :--

उत्पादन भुल्क को छोड़कर रेयन टायर धागें/कार्ड/फैब्रिक्स की कारखाने से निकलते.समय की कीमत

*		 		धागा		ते किग्रा०) रैदिक्स
सुपर 2 माल	•	•	·	12.25	13.00	13.50
भुपर 1 माल	•	ı		10.25	11.00	11.50

^{2.} सरकार ने उपरोक्त संकल्प में यह भी वताया था कि 1971 की तीसरी तिमाही के प्रारम्भ में मांग सिन्नाई/बाजार की जो स्थित रहेगो, उपना विस्तेषण किया जायेगा ताकि 31-12-71 के बाद की नों का निर्धारण किया जा गरे। आरत सरकार ने टैरिफ कमोजन से यह विक्तिपण करने का अपूरोध किया है। जब तक रिपोर्ड नहीं प्रा जाती, तब तक के लिए सरकार ने उपरोक्त कहिका 1 में दी गई की मतों की जारी रखने का थितिश्वय किया है।

के० किशोर, संयुक्त सचिव।